भारत का बैंकिंग परिदृश्य*

दीपक मोहंती

मैं इस विशिष्ट पैनल में शामिल होने का अवसर प्रदान करने के लिए इंडियन चेंबर आफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री राजीव मूंदड़ा और महा निदेशक श्री राजीव सिंह को धन्यवाद देता हूं. इंडियन मर्चेंट चेंबर आफ कॉमर्स वर्ष-दर वर्ष ऐसे बैंकिंग सम्मेलनों के जरिये बैंकिंग उद्योग, कंपनी क्षेत्र तथा वित्तीय विनियामकों के अनुभव और विशेषज्ञता को एक साथ लाकर बैंकिंग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है. इस वर्ष के सम्मेलन में भी मैं यह देख रहा हूं कि भारतीय बैंकिंग पर विचार-विमर्श के लिए संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ यहां मौजूद हैं.

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2000 का दशक घटनाओं से भरा रहा है. हमने जीडीपी वृद्धि में तेजी देखी, जहां 2004-08 के दौरान भारत में औसत वार्षिक उत्पादन वृद्धि 8.7 प्रतिशत के अपने उच्चतम स्तर तक जा पहुंची थी. इसके साथ ही बचत और निवेश में भी तीव्र वृद्धि हुई. इसी समय हमें उस वैश्विक वित्तीय संकट से भी जूझना पड़ा जिसके दुष्प्रभाव अभी तक दिखाई पड़ रहे हैं. पिछले दो वर्षों में आर्थिक संवृद्धि की गति धीमी हुई और मुद्रास्फीति भी काफी उच्च स्तर पर बनी रही, हालांकि 2013-14 के चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में इसमें कुछ उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हुआ है. इन सभी घटनाओं का बैंकिंग पर प्रभाव पड़ा है.

इस आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, मैं पिछले 12 वर्षों के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करूंगा क्योंकि वित्त अनिवार्यतः आर्थिक प्रगति से संबद्ध रहता है. इसके बाद मैं पूर्वी क्षेत्र के विशेष संदर्भ में वित्तीय समावेशन पर चर्चा करूंगा क्योंकि यह रिज़र्व बैंक की वर्तमान नीति का महत्वपूर्ण अंग है. बाद में, मैं बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों पर कुछ विचारों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा.

वित्त और संवृद्धि

आर्थिक साहित्य वित्तीय विकास और संवृद्धि के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित करता है. 1960 तथा 1970 के दशक में रेमंड गोल्डस्मिथ, मिकिनन एंड शॉ के प्रवर्तक कार्य ने अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश को बढ़ाने में वित्तीय उदारीकरण के महत्व को रेखांकित किया था जिससे आर्थिक संवृद्धि को बल मिलता है.[1] हाल के अध्ययनों ने पिछले कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारी इस समझ को बल प्रदान किया है कि देश और काल की सीमाओं से आगे जाकर देशों की आर्थिक संवृद्धि को सकारतात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए कौन से रास्ते अपनाए जा सकते हैं.[2] यहां तक कि हाल ही के वैश्विक वित्तीय संकट ने, जिसके कारण काफी जटिल हैं, इस बात को नहीं नकारा कि आर्थिक संवृद्धि की निरंतरता के लिए वास्तविक अर्थव्यवस्था की जरूरतों सहित वित्तीय विकास अनिवार्य है.[3] यह विशेष रूप से हमारी जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जहां औपचारिक वित्तीय क्षेत्र तक पहुंच अभी भी अपर्याप्त है. अब मैं भारत में बैंकिंग पर आता हूं.

हमारे वित्तीय क्षेत्र में बैंक हावी हैं. बैंकों, बीमा कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सहकारी बैंकों, पारस्परिक निधियों तथा अन्य लघुतर वित्तीय संस्थाओं से युक्त वित्तीय प्रणाली की कुल आस्तियों में 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा वाणिज्य बैंकों का है.[4] बैंकों की कुल आस्तियों की वृद्धि से परिलक्षित बैंकिंग विस्तार वैश्विक वित्तीय संकट के गहन होने तक, जिसने व्यापार, वित्त और विश्वास माध्यमों के जरिये भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, बहुत तेज गति से हो रहा था. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बैंकों की आस्तियां 2000-01 के 60 प्रतिशत से बढ़ कर 2008-09 तक 93 प्रतिशत पर जा

---

* कोलकाता में 18 मई 2013 को आयोजित पांचवे इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स बैंकिंग सम्मिट में श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया व्याख्यान

[1] मेकिनन आर आइ (1973)मनी एंड केपिटल इन इकॉनामिक डेवलपमेंट, वाशिंगटन डीसी ब्रूकिंग्स इंस्टिट्यूसन : शॉ ई एस (1973) फाइनेंशियल डीपनिंग इन इकॉनामिक डेवलपमेंट, न्यूयार्क. आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

[2] सी. लेविन, रोस, नॉर्मन लो लोयजा और थोर्सटन बेक (2000). फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड ग्रोथ : केजुएलिटी एंड काजेज़. मोनेटिरी इकॅनामिक्स जर्नल, खंड 46, अंक 1 तथा डेमिर्ग्युं कुंट. असली एंड रोस लेविन (2004) संस्करण. फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड इकॉनामिक ग्रोथ.: ए क्रॉस कंट्री कंपेरीज़न आफ बैंक्स, मार्केट्स एंड डेवलपमेंट. एमआइटी प्रेस.

[3] जबकि संकट से मिली शिक्षा का अभी भी आकलन किया जा रहा है, आइएमएफ ने इसके लिए वैश्विक कम ब्याज दरों तथा लीवरेज निर्मिती के अलावा विनियमन और पर्यवेक्षण में कमियों और जोखिम प्रबंधन की असफलता को प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना है.(वर्ल्ड इकॉनामिक आउटलुक, अप्रैल 2009. आइएमएफ)

[4] भारतीय रिज़र्व बैंक(2012). वार्षिक रिपोर्ट 2011-12, मुंबई.

चार्ट 1. वैश्विक वित्तीय संकट से बैंकिंग आस्तियों के विस्तार में कमी आयी

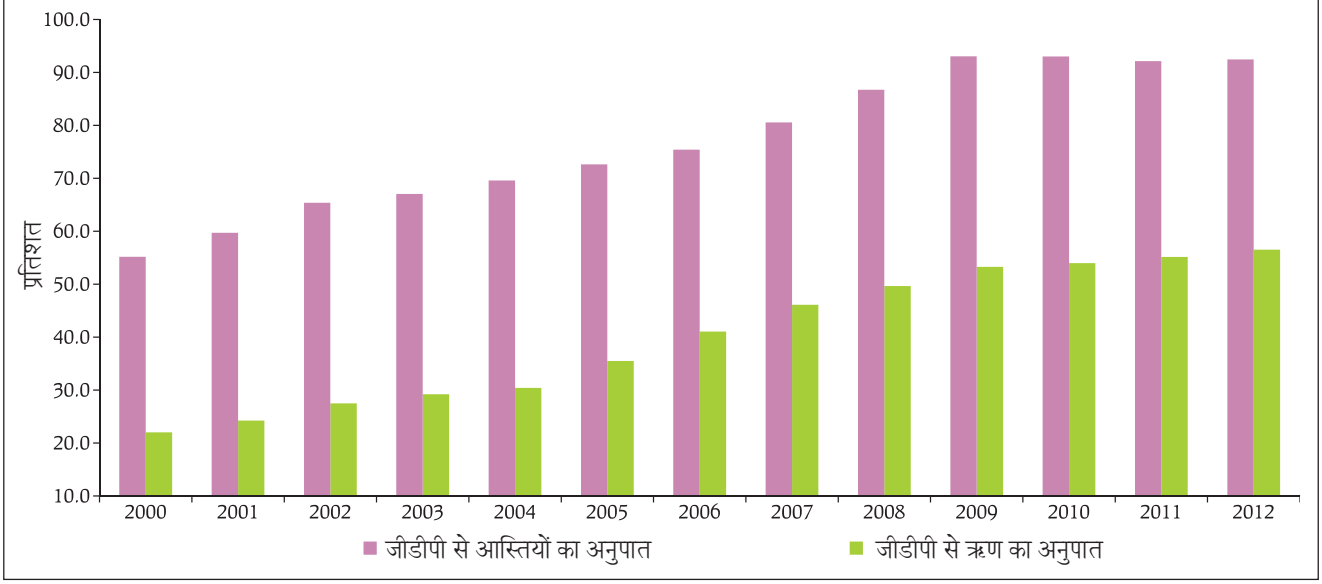

पहुंची, लेकिन उसके बाद यह थम गई. इसी अवधि में, जीडीपी से बैंक ऋण का अनुपात दुगुने से अधिक बढ़ कर 24 प्रतिशत से 53 प्रतिशत हो गया, लेकिन आगे के वर्षों में लगभग उसी स्तर पर बना रहा(चार्ट 1.).

बैंकिंग क्षेत्र का विकास अर्थव्यवस्था के निष्पादन से प्रभावित हुआ, जो बैंकिंग कारोबार में वृद्धि और वास्तविक जीडीपी वृद्धि के बीच घट-बढ़ से प्रतिबिंबित होता है (चार्ट 2). यह उल्लेखनीय है कि 2007-08 तक की अवधि समेकन की अवधि भी थी जब केंद्र और राज्य सरकारों का सम्मिलित राजकोषीय घाटा 2000 के प्रारंभ के 9 प्रतिशत से अधिक से घट कर 2007-08 में 4 प्रतिशत पर आ गया (चार्ट 3). सरकारी उधारों की जरूरत में लगातार कमी होने से वाणिज्य क्षेत्र को गैर-मुद्रास्फीतिकारक तरीके से अधिक ऋण देने का रास्ता खुला.

जहां संकट की अवधि के बाद वित्तीय विस्तार में कमी आई है, वहीं भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने उल्लेखनीय मजबूती और स्थिरता दिखाई है. वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान समय पर

चार्ट 2 : आर्थिक संवृद्धि के अनुरूप बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार

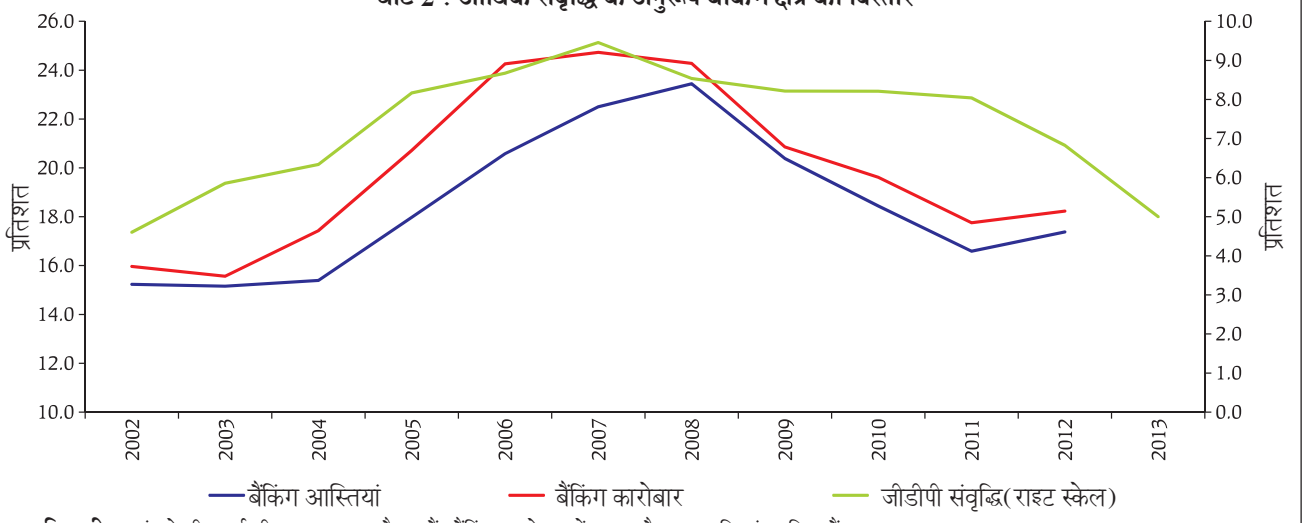

टिप्पणी : आंकड़े तीन वर्ष की घट-बढ़ का औसत हैं. बैंकिंग कारोबार में ऋण और जमाराशियां शामिल हैं.

स्रोत : हैंडबुक आफ स्टेटिस्टिक्स ओन इंडियन इकॉनामी. सांख्यकीय सारणियां

चार्ट 3 : संकटपूर्व अवधि में राजकोषीय समेकन से वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण में वृद्धि

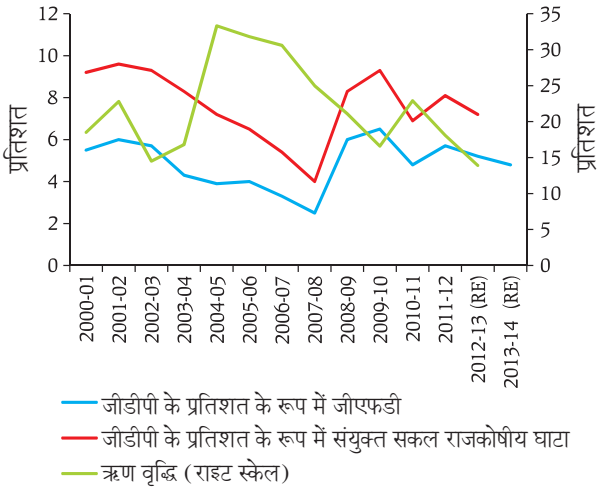

उठाए गए प्रति-चक्रीय विवेकशील और मौद्रिक कदमों से बैंकिंग क्षेत्र बिना जरा भी आहत हुए पार निकल गया.

अधिकांश निर्देशक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता की ओर इशारा करते हैं. सकल और बैंक-समूह स्तर पर जोखिम-आधारित आस्तियों से पूंजी अनुपात 2001 से 9 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम तथा 8 प्रतिशत के अंतर्राष्ट्रीय न्यूनतम मानदंड से ऊपर बना रहा (चार्ट 4).

आस्ति गुणवत्ता में 2000 के दशक के दौरान धीमी गति से सुधार होता रहा. उदाहरण के लिए, सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियों का अनुपात 2000-01 के 12 प्रतिशत से घट कर 2007-08 में 2.4 प्रतिशत रह गया. उसके बाद, पहले यह विदेशी बैंकों और बाद में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में दिसंबर 2012 में बढ़ कर 3.7 प्रतिशत पर पहुंच गया (चार्ट 5).

यद्यपि भारतीय बैंक अनर्जक आस्तियों और सीआरएआर के रूप में ब्रिक्स सहित कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले अच्छी स्थिति में हैं, तथापि इसमें सुधार की काफी गुंजाइश है (सारणी 1).

बैंकिंग-कार्यकुशलता

वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र की कार्यकुशलता और लाभप्रदता में सुधार लाना रहा है. इस संबंध में, ब्याज दर ढांचे को पूरी तरह अविनियमित किया गया. सांविधिक चलनिधि अनुपात तथा आरक्षित नकदी अनुपात के जरिये बैंक-संसाधनों पर पूर्वाधिकार में काफी कमी लाई गई. निर्यात ऋण पुनर्वित्त, सीमांत स्थाई सुविधा तथा चलनिधि समायोजन सुविधा बढ़ाई गई जिससे केंद्रीय बैंक चलनिधि पर बैंकों की निर्भरता में पर्याप्त कमी आई. साथ ही, शाखा लाइसेंसीकरण में छूट दी गई और विवेकशील मानदंडों को सख्त बनाया गया. इसके अलावा, बैंकों ने प्रौद्योगिकी को ज्यादा से ज्यादा अपनाया तथा मानव संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया. जैसाकि विभिन्न निर्देशकों से स्पष्ट है, इससे बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ाने में बहुत सहायता मिली.

चार्ट 4 : बैंक पूंजी सांविधिक न्यूनतम से ऊपर रही

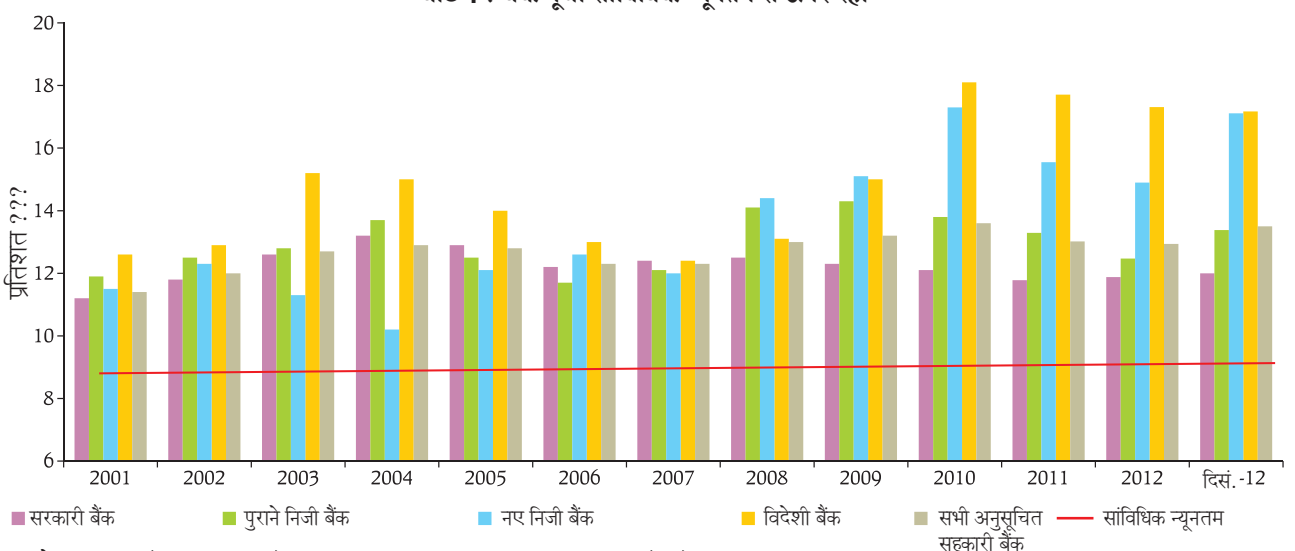

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट के विभिन्न अंक, समष्टि-आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियां 2012-13

चार्ट 5 : अनर्जक आस्तियों में 2000 के दशक में धीमी गिरावट के बाद 2011 से वृद्धि हुई है

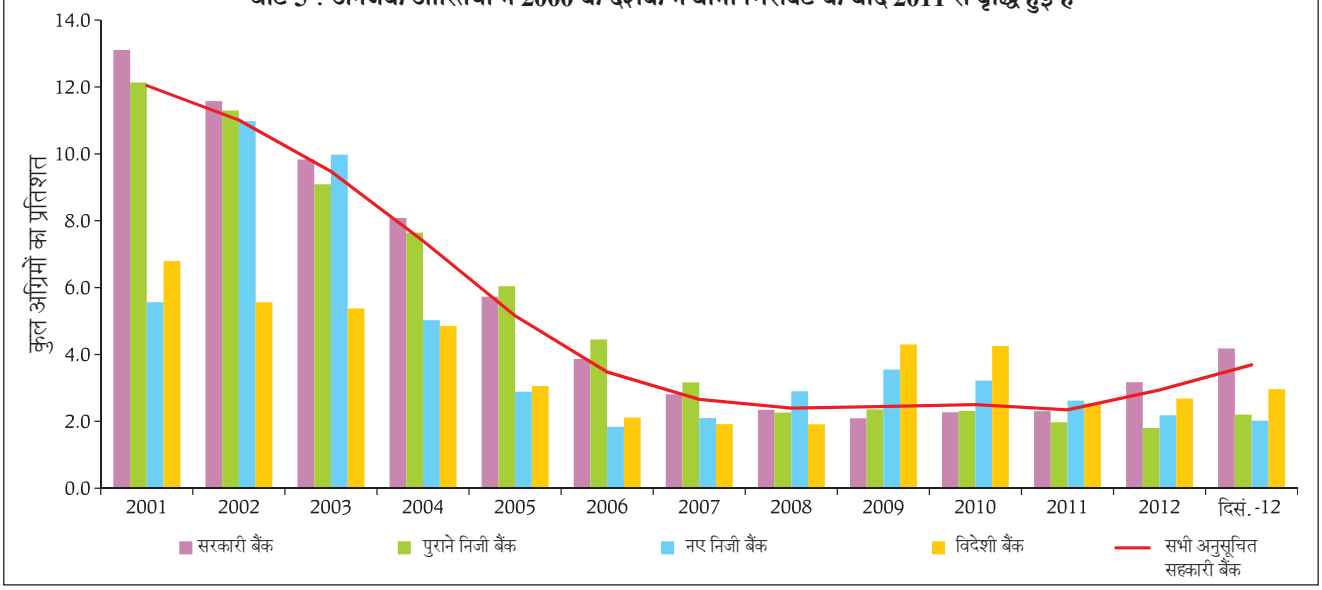

संकट की अवधि के बाद भी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता आस्तियों पर लाभ के रूप में लगभग 1.0 प्रतिशत पर बनी रही. बैंकों ने आय से लागत अनुपात, प्रति कर्मचारी कारोबार और प्रति शाखा कारोबार जैसे कार्यकुशलता निर्देशकों के जरिये उल्लेखनीय सुधार दर्शाया है. लेकिन, निवल ब्याज मार्जिन में वृद्धि हुई जिससे आबंटनीय दक्षता में गिरावट का संकेत मिलता है (सारणी 2). अब मैं विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र के संदर्भ में वित्तीय समावेशन पर चर्चा करूंगा.

सारणी 1: वित्तीय सुदृढ़ता के संकेतक, 2012

क्रम सं.	देश	सकल अग्रिमों के % के रूप में कुल एनपीए	सीआरएआर (%)
	चयनित उन्नत देश		
1	जर्मनी	3.0*	17.9
2	जापान	2.4	14.2
3	यू.के.	4.0	15.7
4	यू एस ए	3.9	15.3
	ब्रिक्स		
5	ब्राजील	3.5	16.7
6	रूस	6.0	13.7
7	*भारत*	*3.6*	13.6
8	चीन	1.0	12.9
9	द. अफ्रीका	4.0	15.8
	ई एम ई		
10	इंडोनेशिया	1.8	17.3
11	कोरिया	1.6	14.1
12	मेक्सिको	2.4	16.0
13	टर्की	2.7	17.9

सीआरएआर: जोखिम भारित आस्तियों से पूंजी अनुपात
*: आंकड़े 2011 से संबंधित हैं
स्रोत : आइएमएफ, वित्तीय सुदृढ़ता निर्देशक

वित्तीय समावेशन

उच्च आर्थिक संवृद्धि बनाए रखने के लिए यह जरूरी कि समाज के वित्तीय रूप से वंचित लोगों को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में लाया जाए. इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं ताकि बिजनेस करेस्पोंडेंट मॉडल के जरिये 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों के दरवाजे तक औपचारिक बैंकिंग को ले जाया जा सके. बिजनेस करेस्पोंडेंट बैंकों के एजेंट के रूप में आधारभूत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं. इसी प्रकार, बैंकरहित क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को शाखा प्राधिकरण योजना में प्रोत्साहन प्रदान किया गया है, अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों को सरल बनाया गया है, प्रौद्योगिकी उन्नयन लाया गया है, वित्तीय शिक्षण अभिमुख कार्यक्रम चलाए गए हैं ताकि वित्तीय समावेशन के प्रति जागरूकता आ सके और इसे बल मिल सके. इन उपायों के प्रारंभिक प्रभाव सकारात्मक रहे हैं. जैसे ही इन गतिविधियों में और बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से सामाजिक लाभों के अंतरण के काम में तेजी होगी, वैसे ही बैंकिंग कारोबार में भारी वृद्धि की संभावनाएं बनेंगी. हालांकि, वित्तीय समावेशन का पता लगाने के लिए हमारे पास खुद के स्रोत उपलब्ध हैं, तथापि जनसंख्या गणना के माध्यम से बैंकिंग तक पहुंच की उपयोगी जानकारी हासिल होती है. इसके अनुसार 2011 के मात्र 35 प्रतिशत के मुकाबले 2011 में 59 प्रतिशत घरों की बैंकिंग तक पहुंच हो

सारणी 2 : बैंकिंग कार्यकुशलता के चयनित मानदंड

वर्ष - मार्च अंत	आस्तियों पर लाभ (%)	निवल ब्याज मार्जिन (%)	लागत-आय अनुपात (%)	प्रति कर्मचारी कारोबार (लाख रुपये)*	प्रति शाखा कारोबार (लाख रुपये)*
2001	0.54	3.1	25.9	2.1	34.7
2002	0.82	2.8	22.3	2.5	39.5
2003	1.05	2.9	22.1	2.8	43.0
2004	1.21	3.1	23.7	3.1	47.7
2005	0.97	3.1	26.1	3.5	53.6
2006	0.96	3.0	26.8	4.1	62.6
2007	1.00	2.9	24.0	4.6	68.6
2008	1.10	2.6	21.0	5.6	79.8
2009	1.10	2.6	19.2	6.5	90.1
2010	1.01	2.5	20.2	7.1	92.1
2011	1.06	2.9	21.6	7.7	99.5
2012	1.05	2.9	18.5	8.3	99.3

* 2004-05 मूल्यों पर

टिप्पणी: निवल ब्याज मार्जिन- औसत कुल आस्तियों से निवल ब्याज आय से संदर्भित है. आस्तियों पर लाभ- औसत कुल आस्तियों से निवल लाभ दर्शाता है. आय से लागत के अनुपात की गणना कुल आय प्रतिशत से परिचालन लागत के रूप में की गई है.

स्रोत: भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी सारणियां, विभिन्न अंक, भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकी विवरणियां, भारतीय रिज़र्व बैंक.

चुकी थी. पूर्वी क्षेत्रों में भी इस संबंध में काफी सफलता मिली है. इन क्षेत्रों में वर्ष 2001 में 29 प्रतिशत घरों की ही बैंकों तक पहुंच थी, जबकि 2011 में यह प्रतिशत बढ़ कर 47 पर पहुंच गया.लेकिन यह क्षेत्र अखिल भारतीय औसत के मुकाबले अभी भी काफी पीछे चल रहा है(सारणी 3).

वर्ष 2001 में प्रति बैंक शाखा अखिल भारतीय औसत जनसंख्या 15,600 थी जो 2012 तक तेजी से घट कर 12500 पर आ गई. इससे यह पता चलता है कि बैंक शाखा नेटवर्क में वृद्धि हुई है. पूर्वी क्षेत्र में 2001 से प्रति बैंक शाखा जनसंख्या में कमी आई है, लेकिन यह अखिल भारतीय औसत से कम है. इसका मतलब यह हुआ कि इस क्षेत्र में बैंक विस्तार की पर्याप्त संभावना मौजूद है.

निष्कर्ष

मैं अपनी बात भावी चुनौतियों के जिक्र के साथ समाप्त करूंगा.

पहली बात तो यह है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए आस्ति-गुणवत्ता की गिरावट तत्काल चिंता का विषय है. अधिक चिंता की इसलिए कि हाल के वर्षों में बैंकों के ऋणों में आधारभूत सुविधा और आवासन जैसे दीर्घावधि ऋणों की संख्या बढ़ी है. हालांकि समष्टि-आर्थिक नीतियों में सुधार तथा आर्थिक संवृद्धि में अपेक्षित सुधार से जोखिम में कुछ कमी आने में सहायता मिलेगी, तथापि बैंकों को अपनी आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गहन प्रयास करने होंगे.

दूसरी बात यह है कि हालांकि अन्य देशों की तुलना में भारतीय बैंकों की कार्यकुशलता सभी पैमानों में बेहतरी दर्शाती है, तथापि निवल ब्याज मार्जिन अपेक्षाकृत काफी अधिक है. बैंकों को अपनी उत्पादकता में और वृद्धि करनी होगी ताकि जमाकर्ताओं और ऋणकर्ताओं के बीच मध्यस्थता संबंधी लागत को कम किया जा सके. साथ ही, मौद्रिक अंतरण में सुधार लाने के लिए अनर्जक आस्तियों में भी कमी लानी होगी.

तीसरी बात यह है कि चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च संवृद्धि के रास्ते पर वापस लौट रही है, ऋण के लिए मांग में अवश्य वृद्धि होगी. इसके परिणामस्वरूप, बैंकिंग विस्तार के लिए अधिक पूंजी की जरूरत होगी. साथ ही, चूंकि बॉसल III की अपेक्षाएं लागू कर दी गई हैं, अतः पूंजी की जरूरत और भी बढ़ेगी. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जून 2012 में किए गए प्रारंभिक मूलयांकन ने यह दर्शाया है कि उच्चतर पूंजी मानदंडों को पूरा करने के लिए भारतीय बैंक समग्रतः अच्छी स्थिति में हैं. रिज़र्व बैंक के मोटे अनुमान के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 2.65-2.75 ट्रिलियन रुपये के अलावा 1.4-1.5 ट्रिलियन रुपये की गैर-ईक्विटी पूंजी के रूप में सामान्य ईक्विटी की जरूरत होगी क्योंकि 2018 तक बासल III का पूरा अनुपालन

सारणी 3 : बैंकिंग तक पहुंच के निर्देशक

मद	अखिल भारतीय			पूर्वी क्षेत्र		
	2001	2011	2012	2001	2011	2012
बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले घर (प्रतिशत)	35.2	58.7	ॐ	28.8	47.3	ॐ
प्रति-शाखा जनसंख्या (000)	15.6	13.3	12.5	19.5	18.1	17.3
प्रति 1000 जनसंख्या पर खातों की संख्या (ऋण)	51	100	106	37	54	54
प्रति 1000 जनसंख्या पर खातों की संख्या (सभी जमाराशियां)	416	669	734	321	476	540
प्रति 1000 जनसंख्या पर खातों की संख्या (बचत जमाराशियां)	272	516	571	202	367	423
प्रति व्यक्ति बकाया ऋण (₹ 000)	5.2	33.7	39.1	2.0	12.1	13.9
प्रति व्यक्ति कुल जमाराशियां (₹ 000)	9.2	44.5	49.4	5.5	22.8	26.5

स्रोत : भारिबैं (जमाखातों की संख्या, ऋण खातों की संख्या, बकाया ऋण तथा बकाया जमाराशियों के लिए) रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिशनर आफ इंडिया का कार्यालय (जनसंख्या और घरों संबंधी आंकड़ो के लिए)

किया जाना है. अतः इन पूंजी मानदंडों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां बनानी होंगी.

चौथी बात यह है कि वैश्विक वित्तीय संकट के पनपने का एक मुख्य कारण जरूरत से ज्यादा लीवरेज का होना था. हालांकि बैंकिंग प्रणाली में ठीक-ठाक लीवरेज मौजूद है, तथापि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंकों को बॉसल समिति के प्रस्तावों के लंबित होने तक 4.5 प्रतिशत का न्यूनतम टीयर I लीवरेज अनुपात बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए. बैंकों के लिए विवेकसम्मत होगा कि वे अंतरिम अवधि में अपनी लीवरेज संबंधी स्थिति में कमी न आने दें.[5]

पांचवी बात यह है कि नए बैंकों के आगमन के साथ बैंकिंग क्षेत्र के विस्तार का प्रस्ताव है. रिज़र्व बैंक ने नए बैंकों के लिए पहले ही आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं. साथ ही, जैसाकि मई 2013 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में इंगित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में बैंकिग ढांचे पर चर्चा पेपर तैयार कर रहा है जिसे जनता के लिए सार्वजनिक किया जाएगा. अर्थव्यवस्था की संवृद्धि के साथ बैंकिंग क्षेत्र के विकास से न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी बल्कि वित्तीय समावेशन को लागू करने में भी सहायता मिलेगी.

इसके साथ ही, मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं.

धन्यवाद.

[5] डी.सुब्बाराव - (2012) ''अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय संदर्भ में बासल III - दस प्रश्न जिनके उत्तर हमें जानने चाहिए''. एफआइसीसीआइ-भारतीय बैंक संघ द्वारा मुंबई में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण